नव भारत
संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

आस्था की भीड़ के बीच व्यवस्था का पतन

सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में हाल ही में जो भगदड़ हुई, उसने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम एक सभ्य समाज के रूप में जनसुरक्षा को लेकर अब भी गंभीर नहीं हो पाए हैं? इस त्रासदी में सात लोगों की असमय मौत हुई. यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह एक मानवजनित विफलता थी, जिसे रोका जा सकता था, टाला जा सकता था, यदि नियोजन होता, समन्वय होता और संवेदनशीलता होती.

कावड़ यात्रा के इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु उमड़े. उनमें से अनेक बिना पंजीकरण के आए. यह स्पष्ट करता है कि आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के बीच न तो किसी प्रकार की पूर्व तैयारी थी, और न ही आपसी समन्वय का कोई ढांचा. जब लाखों लोगों के एकत्र होने की सूचना पहले से हो, तो क्या यह प्रशासन का कर्तव्य नहीं बनता कि वह सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, जलापूर्ति, और ट्रैफिक नियंत्रण की प्रभावी योजना बनाए? दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस घटना ने हमें यह सोचने पर विवश किया है कि क्या धार्मिक आयोजनों की सफलता केवल भीड़ जुटाने से तय होती है? क्या हमारे धार्मिक केंद्रों में 'आस्था' का अर्थ व्यवस्था से विमुख होना है? और क्या हमारी प्रशासनिक प्रणाली तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक किसी आयोजन की भयावह परिणति सामने न आ जाए? यह त्रासदी केवल भीड़ की वजह से नहीं हुई, बल्कि आयोजन की कमी, जिम्मेदारी के अभाव और अव्यवस्था के सामूहिक गठजोड़ से हुई है. 7 मौतें यह भी दर्शाती हैं कि आयोजन स्थल पर न तो प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध थी और न ही जल वितरण की समुचित व्यवस्था. क्या यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं है?

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और जांच की घोषणा जरूर एक प्रारंभिक क़दम है, लेकिन यह घटना किसी भी तरह से 'साधारण भूल' नहीं कही जा सकती. यह एक सिस्टम की असफलता है, जिसके दोषियों को केवल जांच तक सीमित न रखते हुए, सख्त कार्रवाई के दायरे में लाना होगा. केवल आयोजन रोकना, या पंडाल हटाना ही समाधान नहीं है, यह आवश्यक है कि ऐसे आयोजनों के लिए एक स्थाई प्रोटोकॉल बनाया जाए, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ऑनलाइन सूचना प्रणाली, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, भीड़ नियंत्रण की तकनीक और प्रशिक्षित वालंटियर्स की टीम की पूर्व व्यवस्था हो. केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे देशभर के धार्मिक आयोजनों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें, जो किसी भी आयोजन को धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सुरक्षा के ढांचे में बांध सके. इससे आयोजनों की गरिमा भी बनी रहेगी और जनजीवन भी सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा इंदौर भोपाल जैसे व्यस्त मार्ग पर जिस तरह से घंटों जाम लगा रहता है वह भी चिंता का विषय है. इस संबंध में आयोजकों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के भी अपने दायित्व हैं जिनका निर्वहन योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए.

कुबेरेश्वर धाम की यह घटना पहली बार नहीं हुई. जाहिर है आयोजकों और प्रशासन ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया था, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. बहरहाल, कुबेरेश्वर की यह घटना हमें झकझोरती है, न केवल मृतकों के परिवारों के दर्द से, बल्कि इस सच्चाई से भी कि जब व्यवस्था श्रद्धा के सामने असहाय हो जाती है, तब ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं करता. अब वक्त है, सिर्फ श्रद्धा की नहीं, जिम्मेदारी की भी परिभाषा गढ़ने का.

राष्ट्रीय एकता का प्रतीक राखी

प्रो. विवेकानंद तिवारी
अध्यक्ष, आंबेडकर पीठ
एचपीयू, शिमला

बंगाल विभाजन का विरोध विस्फोटक और सर्वव्यापी था. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की और जनता से सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया, जिससे औपनिवेशिक सरकार को सबसे ज्यादा चोट पहुँची. विदेशी कपड़ों का सामूहिक दहन एक आम बात हो गई. लेकिन बंगाल में बाकी सब चीजों की तरह, इस विरोध ने भी बंगाल के महानतम प्रतीक, रवींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में एक अनोखा रूप धारण कर लिया.

टैगोर ने विभाजन के दिन, 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया था - उस दिन बंगाली घरों में खाना नहीं पकाया जाएगा. बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के बंधन को दर्शाने के लिए, टैगोर ने राखी को चुना, जो एक पवित्र धागा है जो बहन द्वारा भाई की कलाई पर उसकी रक्षा के बदले में बाँधा जाता है. परंपरागत रूप से, बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती थीं, क्योंकि भाई उसके जीवित रहते हुए उसकी रक्षा करने का वचन देता था. इसके बजाय, टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे को राखी बाँधें, जिससे जीवन भर सुरक्षा का एक ऐसा बंधन बने जिसे कोई तोड़ न सके.

टैगोर ने 16 अक्टूबर को अपने दिन की शुरुआत गंगा में डुबकी लगाकर की. गंगा तट से, एक जुलूस उनके साथ सड़कों पर निकला और मिलने वाले सभी लोगों की कलाई पर राखी बाँधी. उत्साही कवि के पास ढेर सारी राखियाँ थीं, लेकिन उनके साथ आए लोगों को लगा कि उन्होंने हद कर दी है जब उन्होंने अपने घर के दक्षिण में स्थित एक मस्जिद में जाकर मौलवियों की कलाई पर राखी बाँधी. टैगोर कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे - सौभाग्य से, मौलवियों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जुलूस आगे बढ़ता रहा. सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी. टैगोर के साथ चल रहे लोग एक गीत गा रहे थे जो उन्होंने इस अवसर के लिए विशेष रूप से लिखा था, जिसमें ईश्वर से बंगाल की सुरक्षा और अखंडता की प्रार्थना की गई थी. छठों से महिलाएँ जुलूस पर मुस्कुरे छिड़क रही थीं और शंख बजा रही थीं.

उसी दोपहर, फेडरेशन हॉल की आधारशिला रखी गई - एक भव्य भवन जो दो बंगालों की एकता का प्रतीक था. बैरिस्टर आनंद मोहन बोस को बैठक की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन वे वृद्ध और बीमार थे, इसलिए टैगोर ने उनका भाषण पढ़ा. वहाँ से दिन का दूसरा जुलूस शुरू हुआ, फेडरेशन हॉल से बागबाजार स्थित पशुपति और नंदलाल बसु के घर, भव्य बसु बटी तक. यहाँ राष्ट्रीय कोष की घोषणा की गई और जनता से योगदान माँगा गया. यह कोष योग्य छात्रों को प्रायोजित करेगा और बंगाली उद्यमियों को वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा. इससे, बंगालियों को आशा थी कि समय के साथ विदेशी आयातों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक वस्तुएँ स्वदेश में ही उत्पादित होने लगेंगी.

मजूमदार ने अपनी पुस्तक टैगोर बाय फायरसाइड में लिखा है, उन्होंने रक्षाबंधन की धार्मिक परंपरा को विविधता में एकता के धर्मनिरपेक्ष मूल भाव में बदल दिया और बंग भंग का विरोध किया. एक ही धागा समुदायों को एक साथ बुनता है उस समय के एक प्रभावशाली नेता, टैगोर ने अपने साथी नागरिकों से अपनी सांप्रदायिक पहचान से ऊपर उठकर एकता में एक-दूसरे को गले लगाने का आह्वान करने में अपना पूरा प्रयास किया. जैसा कि अनुमान था, इस साधारण सूत्र ने लाखों भारतीयों की भावनाओं को एक सूत्र में पिरोने में मदद की. चाहे सड़कें हों या सामुदायिक भवन, सैकड़ों हिंदू और मुसलमान एक-दूसरे को राखी बांधने के लिए एकत्र हुए, जो ब्रिटिश सरकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध का प्रतीक था.

अगले छह वर्षों तक कोलकाता, ढाका और सिलहट में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जब तक कि औपनिवेशिक सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा. 1911 में, अंग्रेजों ने अंततः विभाजन वापस ले लिया, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बड़ी जीत थी. इस जीत के बाद हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, इतिहास के पन्नों के बीच छिपी यह घटना बंगाल और देश के अन्य हिस्सों में सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत उदाहरण बनी हालाँकि विरोध प्रदर्शनों का अपेक्षित प्रभाव पड़ा, लेकिन अंततः बंगाल को एकजुट रखना असंभव साबित हुआ. 1912 में, बिहार, असम और ओडिशा बंगाल से अलग कर दिए गए. इस बार विभाजन भाषाई आधार पर हुआ था. पैंतीस साल बाद, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रक्तपात के साथ, एकीकृत बंगाल का सपना आखिरकार टूट गया.

महाकौशल की डायरी

गोपनीय रिपोर्ट कहीं संगठन से न करा दे छुट्टी....

अविनाश दीक्षित

विधानसभा 2023 और बाद में लोकसभा 2024 में मिली जीत का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जुट गए हैं, खबर है कि पार्ट टाईम काम कर रहे लोगों को अब संगठन में तरजीह नहीं मिलेगी. नए मुखिया के फरमान को लेकर महाकोशल के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिलों में उन जमीनी स्तर के पार्टी नेता- कार्यकर्ता भविष्य के प्रति आशान्वित हो गए हैं, वहीं पार्टी में राजनीति सिर्फ पार्ट टाइम के रूप में करने वाले चिंतित नजर आने लगे हैं.

संगठन से पार्ट टाइम जुड़े होने वाले नेता- कार्यकर्ताओं को सेवाएं कितने दिन की और बर्ची हुई हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन संगठन स्तर पर ऐसे नेता-कार्यकर्ताओं की सूची बनाने की जिम्मेदारी गोपनीय तरीके से बनाकर मुख्यालय भेजने की तैयारियां कर लीं गई हैं. गौरतलब है कि भाजपाई राजनीति का एक प्रमुख केंद्र महाकौशल को माना जाता है जहां से पार्टी का अगला चरण क्या होगा, ये तय किया जाता रहा है. इसलिए आगामी चुनावों में भाजपा कहीं से भी कमजोर न हो इसका मुख्यतः ध्यान अभी से रखा जाने लगा है. वहीं पार्टी के लिए 24 घंटे समर्पित रहने वाले नेता-कार्यकर्ता अपने आप को इस फरमान के बाद से बेहतर स्थिति में पा रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश के नए मुखिया के नजरो-करम उन पर जल्द पड़ेंगे और उन्हें भाजपा में नए पद पर जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगीं. प्रदेश भाजपा के मुखिया हेमंत खंडेलवाल कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम के जरिए अलग-अलग जिलों व शहरों में जाकर संगठन की नब्ज भी टटोल रहे हैं जो कि आगामी चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है.

बात करें जबलपुर भाजपा की तो यहां पार्टी 3 गुटों में विभाजित सी नजर आती है. पहला गुट सांसद आशीष दुबे का, दूसरा लोक निर्माण मंत्री और तीसरा विधायक अभिलाष पांडे का.. इन तीनों गुटों में भाजपा के नेता-कार्यकर्ता अपने-अपने चहेतों के प्रति समर्पित होते नजर आए हैं जो कि संगठन स्तर पर वरिष्ठों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है. संगठन के वरिष्ठों की मानें तो ये गुटबाजी जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा रहेगा नहीं तो आने वाले समय में कहीं ये गुटबाजी पार्टी को नुकसान न पहुंचा दे और विपक्ष इसका फायदा न उठा ले, यह बात भी संगठन स्तर के वरिष्ठों और प्रदेश के नए मुखिया हेमंत खंडेलवाल तक पहुंच चुकी है.

एक-दूसरों के हेलमेट के सहारे मिल गया पेट्रोल....

पहले बच्चों की सुरक्षा के लिए ई-रिक्शा में बच्चों के आवागमन पर प्रतिबंध तो अब आमजन की जिंदगियों की सुरक्षा के लिए बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने का जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश... कलेक्टर दीपक सक्सेना के हाल ही में जारी किए गए ये दोनों आदेश इन दिनों सुर्खियों में हैं. जारी आदेश के पहले दो दिनों में जबलपुर में जो दृश्य देखे गए वो काफी हैरान कर देने वाली रहे.. देखा गया कि अधिकांश पेट्रोल पंपों में एक या दो वाहन चालक हेलमेट लेकर पहुंचे जिसके पीछे लंबी कतार में लगे लोग उन दोनों के हेलमेट के भरोसे ही अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते नजर आए. वहीं कुछ पेट्रोल पम्प के सामने हेलमेट की दुकान सजी दिखीं, जहां से किराए पर हेलमेट दिये जा रहे थे. मतलब साफ था ऐ भाई जरा सकना, आदेश तो जारी हो गया है लेकिन मैं अपना हेलमेट भूल गया, देना जरा, मैं पेट्रोल भरवाकर वापस करता हूं. कुछ इस तरह का नजारा शहर के अधिकांश पेट्रोल पंपों में नजर आया. गौरतलब है कि जबलपुर जिले में बीते कुछ माहों में हुए सड़क हादसों में देखा गया कि जो व्यक्ति हादसे में मृत हुए उनमें अधिकतर लोग सिर पर हेलमेट नहीं पहने थे. अगर ये दो पहिया वाहन चालक सिर में हेलमेट पहने होते तो सिर में चोट नहीं लगती और इन्हें अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता.

अमेरिका की टैरिफ नीति उलटी पड़ेगी

भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ अमेरिकी हितों के खिलाफ

डेयरी उत्पादन में भारत ने अमेरिका-ईयू को पछाड़ा

नई दिल्ली, 08 अगस्त भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च विंग ने एक रिपोर्ट में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि भारतीय सामानों पर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ अमेरिकी हितों के खिलाफ जाएगा और इसका सीधा नुकसान अमेरिकी उपभोक्ताओं को होगा. रिपोर्ट में इस कदम को एक खराब नीति निर्णय बताया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ भारत के साथ व्यापार पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने से अमेरिका और उसके नागरिकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि भारत को अपने किसानों को उन वैश्विक कंपनियों की शिकारी प्रथाओं से बचाना जारी रखना चाहिए, जिनकी नजर भारतीय कृषि बाजार पर है.

कृषि और फार्मा क्षेत्र में भारत की रणनीतिक बढ़त-ध्र रिपोर्ट ने डेयरी क्षेत्र में भारत की प्रगति का हवाला देते हुए बताया कि 2015 से 2024 के बीच भारत ने दूध उत्पादन में यूरोपीय संघ और अमेरिका दोनों को पीछे छोड़ दिया है. इस अवधि में भारत का दूध उत्पादन 155.5 मिलियन टन से बढ़कर 211.7 मिलियन टन हो गया, जो 36 प्रतिशत की वृद्धि है.

फार्मा क्षेत्र में, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से कैंसर, पुरानी बीमारियों और संक्रामक रोगों के इलाज के लिए सस्ती और उच्च-गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए. एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत अमेरिका की लगभग 35 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं की जरूरतों को पूरा करता है. यदि इसमें कोई बदलाव होता है, तो कहीं और क्षमता स्थापित करने में कम से कम 3-5 साल लगेंगे.

अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

अमेरिका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च सालाना लगभग 15,000 है. रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत काफी बढ़ जाएगी. यह भी बताया गया है कि अमेरिकी सरकार के मेडिकेयर और मेडिकेड कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य खर्च का 36 प्रतिशत हिस्सा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जेनेरिक दवाओं पर टैरिफ लगाना सरकार के खर्च को कम करने के उद्देश्य के विपरीत है और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च और निजी जेब से होने वाला खर्च दोनों बढ़ेगा.

2030 तक पूरी तरह हरित होगी जियो

नेट जीरो लक्ष्य के लिए बहु-स्तरीय योजना

23,699 साइट्स पर सौर पैनल लगाए गए

मुंबई, 08 अगस्त (वार्ता) रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसकी दूरसंचार सेवा इकाई रिलायंस जियो वर्ष 2030 तक पूरी तरह से हरित ऊर्जा का इस्तेमाल शुरू कर देगी.

हाल में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने साल 2035 तक नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य रखा है, और इसके लिए वह कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है. रिलायंस जियो वर्ष 2030 तक 100 फीसदी ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने लगेगी. अपने लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी ने 23,699 स्थानों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए हैं जिनसे 212 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है. इसके अतिरिक्त, जियो ने कर्नाटक के बीदर में 35 मेगावाट क्षमता वाला एक केंद्रीकृत सौर संयंत्र भी स्थापित किया है. जियो अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में ऊर्जा दक्षता में आगे है. जीएसएमएआई ने एनर्जी बेंचमार्किंग पर अपनी मार्च 2025 की रिपोर्ट में माना कि जियो की प्रति जीबी ट्रैफिक पर ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का लगभग 30 प्रतिशत है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बताया है कि उसने गुजरात के कच्छ में सौर ऊर्जा प्लांट के लिए भूमि का विकास शुरू कर दिया है. कंपनी की यहां 150 अरब यूनिट बिजली निर्माण की योजना है. कंपनी जल्द ही गुजरात के कांडला में दो हजार एकड़ में ग्रीन कैमिकल के उत्पादन का काम भी शुरू करने जा रही है. कांडला और लकड़िया-1 में दो एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट भी

जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री बढ़ी

नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई में 4.83 प्रतिशत बढ़कर 1,88,891 इकाई पर पहुँच गयी. पिछले साल जुलाई में देश में 1,80,185 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे.

ऑटोमोबाइल डीलर संगठनों के महासंघ (फाडा) द्वारा शुक्रवार को जारी आँकड़ों में बताया गया है कि जुलाई में दुपहिया वाहनों की बिक्री 4.35 प्रतिशत घटकर 1,02,973 इकाई रह गयी. जुलाई 2024 में देश में कुल 1,07,655 दुपहिया वाहन बिके थे.

फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने जुलाई की बिक्री के आँकड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि जुलाई 2025 में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में तेजी जारी रही. दुपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य सेगमेंट में बिक्री बढ़ी है. दुपहिया वाहनों में ईवी की बाजार हिस्सेदारी जुलाई में 7.5 प्रतिशत है. वहीं, तिपहिया श्रेणी में ईवी की बाजार हिस्सेदारी 62.1 प्रतिशत पर पहुँच गयी. यात्री वाहनों के मामले में ईवी की बाजार हिस्सेदारी 4.7 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों में 1.63 प्रतिशत रही.

लाभार्थियों का आवास फायनेंस द्वारा सम्मान

उदयपुर में हुए कार्यक्रम में लाभार्थियों की सफलता का जश्न

आवास फायनेंस के एमडी बोले-हर परिवार को घर देना हमारा लक्ष्य

उदयपुर, 08 अगस्त अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, आवास फायनेंसियर्स, ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया.

यह कार्यक्रम उदयपुर में आयोजित किया गया, जहाँ योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले परिवारों की खुशी में सभी शामिल हुए और उन्हें उनके नए घर की उपलब्धि पर बधाई दी गई.

इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण, सिक्किम सरकार के समाज कल्याण विभाग की सचिव सारिका प्रधान, नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी संजय शुक्ला, और बोर्ड सदस्य प्रभंजन मोहापात्रा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे. इस अवसर पर आवास फायनेंसियर्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ सचिन्दर भिंडर ने कहा, भारत के हजारों परिवारों को उनके स्वयं के घर का सपना साकार होते देखना हमारे लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है. हम न केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल घरों के निर्माण के लिए भी प्रयासरत हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन परिवारों की सफलता को उजागर करना था, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का सपना पूरा किया है.

रूसी तेल खरीद पर सरकार ने नहीं दिए कोई निर्देश : एचपीसीएल

नई दिल्ली, 8 अगस्त. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी एचपीसीएल के चेयरमैन विकास कौशल ने कहा है कि सरकार ने रूसी तेल की खरीद को रोकने या जारी रखने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोलियम कंपनियां केवल आर्थिक आधार पर इस बारे में फैसला कर रही हैं. यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल आयात जारी रखने की वजह से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के बाद आया है, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो जाएगा. कौशल ने कहा कि अप्रैल-जून तिमाही में एचपीसीएल द्वारा रिफाइन किए गए कुल कच्चे तेल में रूसी तेल की हिस्सेदारी 13.2 प्रतिशत थी.

2024 में 99 लाख विदेशी पर्यटक भारत आए : मंत्री

2023 की तुलना में विदेशी पर्यटकों में बढ़ोतरी

भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बढ़ाया संपर्क

नई दिल्ली, 08 अगस्त केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि वर्ष 2024 में 99 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए, जो देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. वहीं, इसी अवधि में 3 करोड़ से अधिक भारतीयों ने विदेश यात्रा की.

पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2024 में कुल 99,51,722 विदेशी पर्यटक भारत आए. यह आंकड़ा 2023 के 95,20,928 और 2022 के 64,37,467 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है. आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक विदेशी पर्यटक संयुक्त राज्य अमेरिका (18,04,586) से आए, इसके बाद बांग्लादेश (17,50,165) और यूनाइटेड किंगडम (10,22,587) का स्थान रहा. सरकार ने यह भी जानकारी दी कि 2024 में 77 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की. सऊदी अरब जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 34,23,711 रही, जबकि 21,43,909 भारतीय नागरिक संयुक्त राज्य अमेरिका गए.

यह डेटा आव्रजन ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया है, जैसा कि पर्यटन मंत्रालय के आधिकारिक बयान में उल्लेख किया गया है.